Supplement—II Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 46-2017] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2017 (KARTIKA 22, 1939 SAKA)

General Review

इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा की वर्ष 2015–16 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

दिनांक 17 अक्तूबर, 2017

No. Admn/431/2015/1SIT/5687.—

1. हरियाणा से इलैक्ट्रानिक्स/आईटी/उद्योग और सॉफ्टवेयर निर्यात

1.1 घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए पंसदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभरा हरियाणा आज अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और कार्पोरेट हाऊस का घर है। विभाग ने बंगलौर और हैदराबाद के बाद देश में गुरुग्राम को तीसरे सबसे बड़े आईटी उद्योग के हब के रूप में उभारने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है।

1.2 एचएसआईआईडीसी ने हरियाणा में चार स्थानों यानि पंचकूला, आईएमटी मानेसर, कुण्डली और राई जिला सोनीपत पर आईटी सैक्टर को बढ़ावा देने के लिए टैक्नोलोजी पार्क/इलैक्ट्रानिक्स हार्डवेयर टैक्नोलाजी पार्क के लिए अवसंरचना विकसित की है।

1.3 एचएसआईआईडीसी ने आईटी उद्योग के लिए "रेडी टू मूव" स्थल के निर्माण के लिए आईएमटी मानेसर में 10–10 एकड़ के 10 प्लाट काटकर आबंटित किए हैं और इनमें से कुछ में तो यह सुविधा पहले ही आरम्भ हो चुकी है।

1.4 सरकार (नगर एवं आयोजना में) अब तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 48 निजी उद्यमों को आईटी/साईबर पार्कस की स्थापना के लिए लाइसेंस दिए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार (उद्योग विभाग में) ने भी आईटी/आईटीईज सैक्टर में अनेक सेज प्रस्तावों की सिफारिश की है। आईटी/आईटीईज सैक्टर में 6 सेज पहले ही चालू हो चुकें हैं।

1.5 इलैक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाईन और मैनुफैक्चिरिंग (ईएसडीएम) सैक्टर के विकास में सहायता करने, उद्यमशीलता परिस्थिति की तंत्र के विकास में सहायता करने, रोजगार के अवसर और कर राजस्व में वृद्धि कर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए नवाचार एवं उत्प्रेरक अभियान चलाने के लिए, जिला गुरुग्राम, तहसील बावल,

उप–तहसील धारूहेड़ा, जिला पंचकूला (बरवाला खण्ड और अन्य औद्योगिक क्षेत्र सहित), जिला यमुनानगर, जिला झज्जर और जिला सोनीपत (राज्य सरकार या इसके स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कुण्डली और राई सहित सभी औद्योगिक क्षेत्र) के क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

1.6 विभाग ने प्रदेश में आईटी और आईटी सक्षम सेवा उद्योग के वर्तमान विकास परिदृश्य को देखते हुए पंचकुला में एसटीपीआई पार्कों की स्थापना के लिए भी कदम उठाए हैं। गुरूग्राम में एस.टी.पी.आई. पार्क चालू होने के अग्रिम स्तर पर है।

1.7 उपरोक्त सुविधाओं के लाभप्रद उपयोग से एक मिलियन से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित करने की उम्मीद है। देशभर के आईटी सैक्टर के 6.8 प्रतिशत रोजगार राज्य के खाते में हैं। प्रदेश के आईटी/आईटीईज सैक्टर में लगभग 1.87 लाख व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

1.8 वर्ष 2015–16 के दौरान हरियाणा से इलैक्ट्रानिक्स एवं आईटी निर्यात अनुमानित लगभग यूएसडी डॉलर 6.8 बिलियन किया गया जबकि वर्ष 2014–15 में यह 6.2 बिलियन यूएसडी डॉलर था।

2. आईसीटी अवसरंचना

2.1 विभाग ने स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क क्रियान्वित किया है। इस नेटवर्क के तहत राज्य मुख्यालय को आन्तरिक व भीतरी डाटा ट्रांसफर/इंटरनेट प्रोटोकोल पर वाइस, विडियो इत्यादि शैरिंग करने जैसी सुविधाओं के लिए सभी जिला मुख्यालयों, 124 खण्डों/उप–मण्डलों/तहसीलों/उप–तहसीलों, हरियाणा सिविल सचिवालय और हरियाणा भवन, नई दिल्ली के साथ जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों के 1180 कार्यालयों को होरिजेंटली इस नेटवर्क पर जोड़ा गया है। स्टेट डाटा सेंटर भी स्थापित किया गया है, जिसका उपयोग सुरक्षित डाटा भण्डारण के लिए, सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी, नागरिक सूचना सेवाएं पोर्टल इत्यादि के लिए सैंट्रल डाटा में उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आईएमटी मानेसर में डाटा सेंटर, यूआईडीएआई डाटा सेंटर की भी स्थापना की गई है।

2.2 सरकारी और निजी क्षेत्रों से सम्बंधित नागरिक केन्द्रीय सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2015–16 के दौरान प्रदेश में 2337 सीएससीज (अटल सेवा केन्द्रों) की स्थापना की गई।

2.3 स्वान, एसडीसी और सीएससी जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना का उपयोग करने के लिए नई परियोजना नामतः स्टेट सर्विस गेटवे (एस.एस.डी.जी.) का क्रियान्वयन भी प्रक्रियाधीन है।

2.4 वर्ष के दौरान निवासियों का लगभग 93 प्रतिशत का आधार नामांकन किया गया। शत–प्रतिशत नामांकन हासिल करने के लिए 209 स्थाई केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

2.5 संयोजकता की पहुंच का विस्तार करने और प्रत्येक ग्राम पंचायत को संयोजकता प्रदान करने के लिए 2956 ग्राम पंचायतों में पीएलबी डक्ट बिछाने का कार्य पूरा किया गया है और 2561 ग्राम पंचायतों में ओएफसी बिछाने का कार्य इस वर्ष के दौरान पूरा हो गया है। नेशनल ओपटिकल फाईबर नेटवर्क द्वारा प्रदान की गई उच्च बैंडविड्थ का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों और गांवों को संयोजकता प्रदान की जा रही है। जिला फरीदाबाद, रेवाड़ी और सोनीपत के 761 गांवों में एनओएफएन को चालू किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एन.के.एन.) को भी स्थापित किया गया है।

3. ई–शासन अनुप्रयोगः

अनेक मिशन मोड और अन्य प्रमुख ई–शासन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैंः–

(i) आबकारी एवं कराधान विभाग के वाणिज्यिक करों का कम्प्यूट्रीकरण।

(ii) स्वास्थ्य विभाग की हस्पताल सूचना प्रबन्धन प्रणाली।

(iii) बिजली विभाग का एपीडीआरपी और

(iv) वित्त विभाग की समेकित वित्त प्रबन्धन प्रणाली (आईएफएमएस)।

इसके अतिरिक्त, परिवहन, राजस्व, पंचायत एवं खजाना विभागों की चालू परियोजनाएं, जो क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है। इस वर्ष के दौरान विभिन्न ई–शासन परियोजनाएं प्रदान की गई है।

4. कौशल विकास कार्यक्रम

राष्ट्रीय डिजिटल कार्यक्रम के तहत 1,32,371 नागरिकों को प्रशिक्षित किया गया है। इलैक्ट्रोनिक्स डिजाइन और मैनुफैक्चरिंग प्रोग्राम में कौशल विकास के तहत आईटी/आईटीईज, इलैक्ट्रोनिक्स एंड टेलीकॉमनिकेशन सैक्टर के 64 कोर्सों में प्रशिक्षित किया गया। हारट्रोन और आईटी विभाग द्वारा आईसीटी के लिए अब तक 90,000 से अधिक निजी व्यक्तियों और 35000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, हारट्रोन नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटिड (एच.के.सी.एल.) द्वारा 205 प्राधिकृत लर्निंग सेन्टर भी स्थापित किये गए हैं।

5. बजट और परिव्यय

4361.40 लाख रुपये के स्वीकृत बजट में से विभाग ने वर्ष के दौरान इलैक्ट्रोनिक्स/आईटी/गतिविधियों में 3135.11 लाख रुपये खर्च किए हैं। भारत सरकार से फण्ड न मिलने के कारण, रिक्त पदों के कारण खर्च में कमी आई। विभाग में कोई राजस्व योजना नहीं है। बहरहाल, आरटीआई अधिनियम और साइबर क्राइम एक्ट के तहत फीस के रूप में 8,13,500/– रुपये की राशि प्राप्त हुई।

6. विभागाध्यक्ष

वर्ष के दौरान रिपोर्ट अधीन निम्न अधिकारियों ने प्रशासनिक सचिव और सचिव के पद का कार्यभर संभालाः–

(क) प्रशासनिक सचिव

(i) श्री देवेन्द्र सिंह, आईएएस

1.4.2015 से 13.10.2015

(ii) श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा, आईएएस

14.10.2015 से 31.3.2016

(ख) सचिव

(i) श्री विजेंद्रा कुमार, आईएएस

1.4.2015 से 31.3.2016

(हस्ता०)...,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

चंडीगढ़:
दिनांक 8–8–2017.

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT FOR THE YEAR 2015-16

The 17th October, 2017

No. Admn/431/2015/1SIT/5687.—

1. Electronics/IT/ITES Industry and Software Export form Haryana

1.1 Having emerged as a preferred investment destination for the domestic as well as international investors, Haryana today is home to a number of multinational Companies and Corporate houses. The Department has done very well with the emergence of Gurugram as the third largest hub of IT Industry in the country after Bangalore and Hyderabad.

1.2 The HSIIDC has developed infrastructure for Technology Park/Electronics Hardware Technology Park to promote IT Sector at four locations *i.e.* Panchkula, IMT Manesar, Kundli and Rai in Sonepat in Haryana.

1.3 The HSIIDC has also carved out and allotted 10 plots of 10 acre each at IMT Manesar for construction of 'ready to move' space for the IT Industry and a few of these facilities have already been commissioned.

1.4 The Government (in Town and Country Planning) till date has granted licenses to 48 private entrepreneurial for establishment of IT/Cyber Parks at various places in the State. In addition to this, the State Government (in Industries Department) has also recommended a number of SEZs proposals in IT/ITEs Sector. Six SEZs In the IT/ITEs Sector have already become operational.

1.5 To aid the growth of the Electronics Systems Design and Manufacturing (ESDM) sector, help development of entrepreneurial ecosystem, drive innovation and catalyze the economic growth of the region by increasing employment opportunities and tax revenues, the area of District Gurugram, Tehsil Bawal, Dharuhera Sub Tehsil, District Panchkula (including Barwala Block and other Ind. Area), District Faridabad, District Palwal, Ambala District, Yamuna Nagar District Jhajjar District and Sonepat District (All industrial areas including Kundli and Rai area approved by the State Government or its local authority) have been notified by Government of India.

1.6 The department has also initiated steps for setting up of STPI Parks at Panchkula looking at the present scenario of growth of IT and IT enabled Services Industries in the State. The STPI Park at Gurugram is in advance stage of commissioning.

1.7 With the gainful utilization of above facilities, it is expected to generate direct or indirect employment opportunities for more than a million persons. The State accounts for 6.8% of the employment in the IT Sector throughout the country. About 1.87 lac persons are working in IT/ITEs Sector in the State.

1.8 During the year 2015-16, Electronics & IT Export are estimated to be about USD$ 6.8 Billion from Haryana as compared to USD$ 6.2 Billion in 2014-15.

2. ICT Infrastructure

2.1 The department has implemented the State Wide Area Network. Under this network, State Head Quarters has been connected with all the District Head Quarters, 124 Blocks/Sub-Divisions/Tehsils/Sub Tehsils, Haryana Civil Secretariat and Haryana Bhawan, New Delhi for facilities such as Inter and Intra data transfer/sharing voice over internet Protocol, Video etc. Beside this, 1180 offices of various departments have been connected horizontally on this network. The State Data Centre has also been set up which is being used at a Central Data repository for secure data storage, online delivery of services, citizen information services portal etc. Besides this, Data Centre, UIDAI Data Centre has also been established at IMT Manesar.

2.2 For delivery of a whole range citizen Centric Services relating the both Government and Private Sector, 2337 CSCs (Atal Seva Kendras) have been established in the State during the year 2015-16.

2.3 To utilize the core infrastructure like SWAN, SDC and CSCs, implementation of a new project namely, State Service Gateway (SSDG) is also under process.

2.4 During the year, about 93% of State Residents have been enrolled for Aadhaar. 209 Permanent Centres have been established to achieve 100% enrolment.

2.5 In order to expend the outreach of the connectivity and provide last mile connectivity to each of the Gram Panchayats, PLB duct laying work in 2956 Gram Panchayats has been completed and OFC laying work in 2561 Gram Panchayats has been completed during the year. In order to ensure proper utilization of high bandwidth provided by National Optical Fibre Network the connectivity is being provided to schools and Gram Sachivalays. The NOFN has been made operational in 761 villages in the District of Faridabad, Rewari and Sonepat. Beside this, National Knowledge Network (NKN) has also been established in the State.

3. e-Governance Applications:

Steps have been taken for implementation of a number of Mission Mode and other major e-Governance Projects. These include: (i) Computerization of Commercial Taxes of Excise & Taxation Department, (ii) Hospital Information management System of the Health Department (iii) APDRP of the power Department, and (iv) Integrated Financial Management Systems (IFMS) of the Finance Department, apart from the ongoing projects of Transport, Revenue, Panchayats and Treasuries, which are at different stages of implementation. Various e-Governance Projects have been awarded during the year.

4. Skill Development Programme:

Under National Digital Literacy Programme 1,32,371 citizens were trained. Under Skill Development in Electronics Design and Manufacturing Programme, 3000 persons were trained in 64 courses in IT/ITES, Electronics & Telecommunication Sector. Till date more than 90,000 private individuals and more 35,000 Government Employees have been imparted training for ICT by Hartron and IT Department. Besides this, 205 authorized learning centres have also been established by Haryana Knowledge Corporation Limited (HKCL).

5. Budget and Expenditure:

Out of the approved budget of Rs. 4361.40 lac, Department has spent Rs. 3135.11 lac during the year in Electronics/IT/ITES activities. Short fall in expenditure due to non-receipt of funds from Government of India and vacant posts. There is no revenue scheme in the department. However an amount of Rs. 8,13,500/- was received as fee under RTI Act, 2005 and Cyber Crime Act.

6. Head of Department:

During the year under report the following held the charge of the post of Administrative Secretary and Secretary:-

(a) Administrative Secretary

(i) Sh. Devender Singh, IAS

1.4.2015 to 13.10.2015

(ii) Smt. Keshni Anand Arora, IAS

14.10.2015 to 31.3.2016

(b) Secretary

(i) Sh. Vijayendra Kumar, IAS

1.4.2015 to 31.3.2016

(Sd.)…,
Principal Secretary to Government Haryana,
Electronics & Information Technology.

Chandigarh:
The 8-8-2017.

55743—C.S.—H.G.P., Chd.